

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 233] No. 233] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 8, 2016/आषाढ़ 17, 1938

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 8, 2016/ASADHA 17, 1938

# वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

# (वाणिज्य विभाग) (पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

### जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2016

### निर्णायक समीक्षा

विषय : यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कतिपय रबड़ रसायनों, अर्थात टीडीक्यू और पीएक्स-13 और चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एमओआर और एमबीटीएस के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरूआत

**फा. सं. 15/5/2016-डीजीएडी**: वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

2. यत: निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 11 मई, 2011 की अधिसूचना सं. 15/14/2009-डीजीएडी द्वारा चीन जनवादी गणराज्य (चीन जन. गण.) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एमओआर और यूरोपीय संघ (ईयू) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीएक्स-13 और टीडीक्यू के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी और इन सिफारिशों के आधार पर चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ के मूल की अथवा वहां से निर्यातित उक्त वस्तुओं पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को राजस्व विभाग, भारत सरकार

3427 GI/2016 (1)

द्वारा उसकी दिनांक 28 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं. 67/2011-सीमाशुल्क के अनुसार जारी रखा गया था। यह शुल्क 27 जुलाई, 2016 तक वैध हैं।

3. इसके अलावा, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं. 15/9/2010 के अनुसार चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एमबीटीएस के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की गई थी और इन सिफारिशों के आधार पर चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित एमबीटीएस पर निश्चयात्मक पाटनरोधीशुल्क को राजस्व विभाग द्वारा उसकी दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 की अधिसूचना सं. 98/2011-सीमाशुल्क के अनुसार जारी रखा गया था। यह शुल्क 19 अक्टूबर, 2016 तक वैध हैं।

### समीक्षा के लिए अनुरोध

- 4. यत: पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार उक्त अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले न हटाया जाए, और यदि शुल्क के समाप्त होने से पहले किसी समीक्षा की शुरूआत नहीं की जाए तो उसे लगाने की तारीख से पांच वर्ष बीत जाने के बाद निष्प्रभावी हो जाता है, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है। उक्त के अनुसार, प्राधिकारी के लिए उपाय की समाप्ति की तारीख से पहले तर्कसंगत समयाविध के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है।
- 5. और यत: अधिनियम और नियमावली के अनुसार उक्त रबड़ कैमिकल के प्रमुख घरेलू उत्पादक अर्थात मै. नोसिल लिमिटेड द्वारा एक याचिका दायर की गई है जिसमें उक्त नामित देशों/क्षेत्रों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित उक्त वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना का आरोप लगाया गया है और यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीएक्स-13 और टीडीक्यू और चीन जन. गण. के मूल के या वहां से निर्यातित एमओआर और एमबीटीएस के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए एक संयुक्त निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

### समीक्षा के आधार

6. इस आधार पर लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया गया है कि संबद्ध देशों/क्षेत्रों से पीएक्स-13, एमओआर और एमबीटीएस का पाटन जारी है और यदि शुल्क हटाया जाता है तो जारी रहने की संभावना है और यूरोपीय संघ से टीडीक्यू के पाटन की पुनरावृति होने की संभावना है जिसका कारण संबद्ध देशों/क्षेत्रों के पास मौजूद अतिरेक क्षमता और अन्य कारक हैं और जैसे कि पिछले 15 महीनों में आयातों की मात्रा और कीमत के रूझानों से स्पष्ट है उक्त वस्तुओं के ऐसे आयातों के कारण क्षति के जारी रहने या पुनरावृति होने की संभावना है। प्राधिकारी को पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की जॉच करने के लिए जॉच की शुरूआत करने हेत् याचिका में पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य मिले हैं।

#### विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

- 7. वे उत्पाद जिन पर शुल्क लागू है रबड़ उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए प्रयुक्त चार विशिष्ट रबड़ रसायन हैं अर्थात पीएक्स-13, टीडीक्यू, एमओआर और एमबीटीएस। इस समीक्षा में केवल ये चार विशिष्ट रबड़ रसायन शामिल हैं और एतदपश्चात इन्हें संबद्ध वस्तु कहा गया है। उत्पादों को याचिका में उनके रासायनिक संघटन और व्यापारिक नामों के अनुसार विस्तार से बताया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा विनिर्मित और नामित देशों/क्षेत्रों में अन्य उत्पादों द्वारा विनिर्मित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है।
- 8. प्राधिकारी ने मूल जॉंच में यह नोट किया कि संबद्ध वस्तु के लिए कोई विशिष्ट आईटीसी एचएस वर्गीकरण नहीं है और विचाराधीन उत्पादों को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम और आईटीसीएचएस वर्गीकरण के सीमाशुल्क वर्गीकरण के विभिन्न उपशीर्षों 38.12.10, 38.12.20 और 38.12.30 तथा 29.34.20 और 29.25.20 (छह अंकीय स्तर पर) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अत: उक्त दर्शाए गए सीमाशुल्क और आईटीसी एचएस वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और वर्तमान जॉंच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं हैं।

### घरेलू उद्योग

9. यह याचिका नोसिल लिमिटेड द्वारा दायर की गई है जो भारत में संबद्ध वस्तु के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में संबद्ध वस्तु के अन्य उत्पादक हैं (क) लैनसेस इंडिया प्रा. लि. (ख) मरकेम लि. और (ग) पीएमसी रबड़ कैमिकल्स इंडिया प्रा. लि.। तथापि, प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार याचिकाकर्ता कंपनी के पास भारत में संबद्ध वस्तु में से प्रत्येक के कुल उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है और इसलिए वह आवेदन दायर करने की योग्यता रखता है। तदनुसार, याचिकाकर्ता कंपनी क्षति जाँच के प्रयोजनार्थ नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं।

### निर्णायक समीक्षा की शुरूआत

10. समीक्षा की जरूरत को सही ठहराते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक साक्ष्य जिनमें पाटन और परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना दर्शाई गई है, के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करते हुए, प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करते हैं तािक इस बात की समीक्षा की जा सके कि क्या संबद्ध वस्तु पर 28 जुलाई, 2011 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 67/2011 और 20 अक्टूबर, 2011 की सं. 98/2011-सीमाशुल्क द्वारा बढ़ाये गये/लगाये गए शुल्क के हटने से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी या उसकी पुनरावृति होगी और क्या शुल्क को जारी रखने की जरूरत है।

#### प्रकिया

11. इस समीक्षा में दिनांक 11 मई 2011 की अधिसूचना सं. 15/14/2009-डीजीएडी और दिनांक 25 जुलाई 2011 की सं. 15/9/2010-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे। वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि अप्रैल, 2015 - मार्च, 2016 (12 महीने) तक की अवधि जाँच अवधि है। तथापि, क्षति जाँच अवधि में 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015 और जाँच की प्रस्तावित अवधि (2015-16) की अवधि शामिल होगी। संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागु होंगे।

### सूचना प्रस्तुत करना

12. संबद्ध देशों/क्षेत्रों में ज्ञात निर्यातकों और भारत में स्थित उनके दूतावासों/प्रतिनिधियों के जरिए संबद्ध देशों/क्षेत्रों की सरकारों और भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातों और प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से निम्नलिखित पते पर संगत सूचना प्रस्तुत करने अलग से सूचित किया जा रहा है:

### निर्दिष्ट प्राधिकारी

# पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय वाणिज्य विभाग जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल

# 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

13. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उक्त अनुरोध का अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना होगा।

#### समय-सीमा

14. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना इस जाँच शुरूआत की अधिसूचना के भेजने की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

15. अत:, सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरूआत की अधिसूचना के भेजने की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना और प्रश्नावली के अपने उत्तर और घरेलू उद्योग की पाटनरोधी उपायों को जारी रखने या अन्यथा संबधी आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

## गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

- 16. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में" गोपनीयता "का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर " गोपनीय "या " अगोपनीय " अंकित होना चाहिए।
- 17. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पाँच (5) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
- 18. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,िजसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है ,पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध / रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि ,आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और/या प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों सभव नहीं है।
- 19. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
- 20. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सुचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

### सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

21. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

### <u>असहयोग</u>

22. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

### (Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

#### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2016

#### **Sunset Review**

Subject: Initiation of Sunset Review of the anti-dumping duty in force on imports of Certain Rubber Chemicals, namely, TDQ & PX-13 originating in or exported from the European Union and MOR and MBTS originating in or exported from the Peoples Republic of China.

- **F. No. 15/5/2016- DGAD**: Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995) as amended from time to time (hereinafter referred to as the Rules:
- 2. WHEREAS the Designated Authority, vide notification No. 15/14/2009-DGAD dated 11<sup>th</sup> May, 2011 recommended continued imposition of the antidumping duties on imports of MOR originating in or exported from the Peoples Republic of China (China PR); and PX13 and TDQ originating in or exported from the European Union (EU) and on the basis of these recommendations definitive antidumping duties, on the above goods originating in or exported from China PR and the European Union respectively, was extended by the Department of Revenue, Govt. of India, vide Notification No. 67 /2011-Customs, dated 28<sup>th</sup> July, 2011. The duties are valid till 27<sup>th</sup> July, 2016.
- 3. Further, continued imposition of antidumping duty on imports of MBTS originating in or exported from China PR was recommended by the Designated Authority, vide notification No. 15/9/2010- DGAD dated 25th July, 2011 and on the basis of these recommendations definitive antidumping duties were extended by the Department of Revenue on MBTS originating in or exported from China PR, vide Notification No. 98/2011-Customs, dated 20<sup>th</sup> October, 2011. The duties are valid till 19<sup>th</sup> October, 2016.

### Request for Review

- 4. Whereas, in terms of Section 9 A (5) the Customs Tariff Act, 1995, read with Rule 23 of the Rules, the antidumping duty imposed under the said Act shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, unless in a review, initiated before the expiry of the duty, the Designated Authority concludes that the cessation of the duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
- 5. And Whereas a petition has been filed by the major domestic producer of the above Rubber Chemicals i.e., M/s NOCIL Limited, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the above goods, originating in or exported from the countries/territories named above and consequent injury to the domestic industry and requesting for initiating a combined sunset review investigation for continuation of anti-dumping duties in force on imports of PX-13 and TDQ originating in or exported from the European Union; and MOR and MBTS originating in or exported from China PR.

#### Grounds for review

6. The request is for continuation of the antidumping duties in force on the grounds that dumping of PX-13, MOR and MBTS from the subject countries/territories have continued and is likely to continue and dumping of TDQ is likely to recur from the European Union if the duties are revoked because of the excess capacities in the subject countries/territories and other factors; and likelihood of continuation or recurrence of injury on account of such imports of the said goods as evidenced by the volume and price trends of imports in the last 15 months. The Authority finds sufficient prima facie evidence in the petition to initiate an investigation to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.

#### **Products under Consideration and Like Article**

7. The products on which the duties are in force are four specific rubber chemicals used in manufacture of rubber products, viz., PX-13, TDQ, MOR & MBTS. This review covers these four specific rubber chemicals only and

hereinafter they have been referred to as subject goods. The products have been described in detail in the petition in terms of their chemical compositions and trade names. There is no known difference between the goods manufactured by the petitioner and the other producers in the countries/territories named.

8. The Authority, in the original investigations, noted that there is no dedicated ITC HS Classification for the subject goods and products under consideration are classified under various subheadings of customs classification heads 38.12.10, 38.12.20 and 38.12.30 as well as under 29.34.20 and 29.25.20 (at six digit levels) of the Customs Tariff Act and ITC HS classification. Therefore, the Customs and ITC HS classifications shown above are indicative only and are in no way binding on the scope of the present investigation.

#### **Domestic Industry**

9. The Petition has been filed by NOCIL Limited., who is the major producer of the subject goods in India. The other producers of the subject goods in India are (a) Lanxess India Pvt. Ltd (b) Merchem Ltd. and (c) PMC Rubber Chemicals India Pvt. Ltd. However, as per information available with Authority the petitioner Company commands a major proportion of the total production of each of the subject goods in India and therefore, commands the standing to file the application. Accordingly, the petitioner Company constitutes the 'Domestic Industry' within the meaning of the Rules for the purpose of injury investigation.

#### **Initiation of Sunset Review**

10. Having satisfied itself, on the basis of the positive *prima facie* evidence submitted by the domestic industry indicating likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury, the Authority hereby initiates a Sunset Review investigation in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of Antidumping Rules, to examine whether the expiry of the duties on the subject goods extended/imposed, vide customs notification No. 67 /2011-Customs dated 28<sup>th</sup> July, 2011 and No. 98/2011-Customs dated 20<sup>th</sup> October, 2011, would likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry and whether continued imposition of duties is warranted.

#### **Procedure**

11. The review will cover all aspects of Notification Nos. 15/14/2009-DGAD dated 11<sup>th</sup> May 2011 and 15/9/2010-DGAD dated 25th July 2011. The period of investigation for the purpose of the present review is from April 2015-Mar 2016 (12 Months). The injury investigation period will however cover the periods 2012-13, 2013-14, 2014-15 and proposed period of investigation (2015-16). The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule supra shall be applicable to this review.

#### **Submission of Information**

12. The known exporters in the subject countries/territories, the Government of the subject countries/territories, through their embassies/representatives in India, and known importers and users of the subject goods in India, are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties
Department of Commerce,
Jeevan Tara Building, 4th Floor
5, Parliament Street
New Delhi -110001

13. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

#### **Time Limit**

- 14. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of communication of initiation of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Antidumping Rules.
- 15. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application

regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the communication of initiation of this Notification.

#### Submission of information on confidential basis

- 16. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
- 17. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all interested parties.
- 18. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible, to the satisfaction of the Authority.
- 19. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
- 20. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

### Inspection of public file

21. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

#### Non-cooperation

22. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as it may deem fit.

A. K. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority